[2009] 6 एस.सी.आर. 63

झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

शिव करमपाल साहू

(सिविल अपील संख्या 2539/2009)

15 अप्रैल, 2009

[**न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति साइरिएक जोसेफ**]

प्रशासनिक कानून:

पॉली निर्णय सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए - सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए परिपत्र पत्र - निर्णय: लाभ उन निर्भर व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता जो मृतक सरकारी कर्मचारी नहीं थे - बिहार सरकार द्वारा 21.9.1987 और 9.8.2000 को जारी किया गया परिपत्र, झारखंड सरकार द्वारा 7.5.2003 को जारी किया गया परिपत्र।

उप-नियमावली - निर्माण - निर्णय: सामान्यतः इसे पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं समझा जाना चाहिए - संदर्भ द्वारा समावेशन का नियम तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक कि स्पष्ट मामला प्रस्तुत न किया जाए।

सेवा कानून:

नियुक्ति - सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति - निर्णय: इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए - ऐसी योजनाओं को व्यापक अर्थ में नहीं लिया जा सकता क्योंकि संवैधानिक योजना यह कल्पना करती है कि सभी व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए विचारित होने के योग्य हैं, उन्हें इसके लिए विचारित होने का अधिकार होगा - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16

बिहार राज्य ने 9.8.2000 को आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के आश्रितों को सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति देने के लिए एक योजना का परिपत्र जारी किया। उत्तरदाता के पिता सरकारी कर्मचारी नहीं थे। उन पर कथित तौर पर 19.5.2000 को चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया था। उत्तरदाता ने 5.11.2000 को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए एक प्रतिनिधित्व दायर किया, जिसे अस्वीकृत कर दिया

गया। हालांकि, 7.5.2003 को झारखंड सरकार, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आई, ने यह नीति निर्णय लिया कि आतंकवादी हिंसा में मारे गए मृतक के आश्रित की नियुक्ति से संबंधित मामला झारखंड राज्य के गठन की तारीख, अर्थात् 15.10.2000 के बाद की हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होना चाहिए। उत्तरदाता ने प्रतिनिधित्व दायर किया जिसे इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि हत्या 19.5.2000 को हुई थी, अर्थात् 9.8.2000 से पहले, इसलिए मामला बिहार सरकार के परिपत्र के दायरे में नहीं आता। उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि हालांकि उत्तरदाता को मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन झारखंड राज्य द्वारा सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के मामले में जारी किए गए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, जो मृत्यु की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर सामान्य मामलों में लागू होते हैं, यह मामला भी इसी श्रेणी में आएगा। इसलिए अपील स्वीकार की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक हमलों में मारे गए या घायल व्यक्तियों के आश्रितों को मौद्रिक मुआवजे के लिए योजना को परिपत्र पत्रों में किए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। ऐसी योजनाओं को व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता क्योंकि संवैधानिक योजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए विचारित होने के योग्य हैं, उन्हें इसके लिए विचारित किया जाएगा। इसलिए, सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए कोई भी नीतिगत निर्णय सख्त व्याख्या का विषय होना चाहिए। [पैराग्राफ 9] [72-बी-ई]

राज्य जम्मू और कश्मीर एवं अन्य बनाम सजाद अहमद मीर (2006) 5 एससीसी 766 और *मुमताज़ युनूस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* 2008 (4) स्केल 637, पर निर्भर।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया परिपत्र पत्र उन निर्भर व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकता जो मृतक सरकारी कर्मचारी नहीं थे। सार्वजनिक रोजगार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो इसके लिए योग्य है। सभी भर्ती उचित अपवादों के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। राज्य द्वारा जारी किया गया परिपत्र संविधान की सार्वजनिक नियुक्ति की योजना से बाहर नहीं हो सकता। इसके अलावा, एक दयालु परिपत्र को उस मामले में विस्तारित नहीं किया जा सकता जिसे स्वयं परिपत्र द्वारा नहीं माना गया था। [पैराग्राफ 11 और 12] [73-सी-एफ]

आधिकारिक लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य (2008) 10 एससीसी 1; *बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह एवं अन्य* (2009) 4 स्केल 282; *मान सिंह बनाम आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी एवं अन्य* 2009 (4*) एससीसी 645; क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचूर बनाम रामानुज मैच उद्योग एआईआर 1985 एससी 278; दीपल गिरिशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा (2004) 5 एससीसी* 385, पर निर्भर।

3.1. अधीनस्थ कानून के निर्माण या आवेदन के मामले में, संदर्भ द्वारा समावेशन का नियम तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक कि इसके लिए स्पष्ट मामला प्रस्तुत न किया जाए। 21.9.1987 का परिपत्र स्वतंत्र है। यह अपने क्षेत्र में कार्य करता है। दोनों परिपत्रों को एक साथ पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि उन्हें पढ़ा भी जा सके, तो सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्तियों के संबंध में सामान्य परिपत्र, जो मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के मामलों पर लागू होते थे, न तो उन नियुक्तियों की अवधि पर विचार करने के लिए और न ही अन्यथा, लाभ देने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए वह अन्यथा योग्य नहीं था। [पैराग्राफ 13] [74-डी-एफ]

भारतीय बैंक प्रबंधन एवं अन्य बनाम रमेशचंद्रन एवं अन्य जेटी 2007 (13) एससी 436, पर निर्भर।

3.2. सामान्यतः, अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं समझा जाना चाहिए। 7.5.2003 का परिपत्र भविष्यात्मक प्रभाव दिया गया था। उत्तरदाता के पिता की मृत्यु 19.5.2000 को हुई। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि 9.8.2000 का परिपत्र भी पूर्वव्यापी प्रभाव में दिया गया था। किसी भी दृष्टिकोण से, चूंकि झारखंड राज्य ने 7.5.2003 के परिपत्र में बिहार राज्य द्वारा जारी किए गए पूर्ववर्ती परिपत्रों को केवल उन मामलों में अपनाया जहां मृत्यु 15.10.2000 के बाद हुई थी, अर्थात् उस तारीख से जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, उच्च न्यायालय ने इस परिपत्र को अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव देने में गंभीर त्रुटि की, जिसे वह सीधे तौर पर नहीं कर सकता था। [पैराग्राफ 14] [75-ए-सी]

मामला कानून संदर्भ:

(2006) 5 एससीसी 766	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 10]**
2008 (4) स्केल 637	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 10]**
(2008) 10 एससीसी 1	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 11]**
(2009) 4 स्केल 282	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 11]**
2009 (4) एससीसी 645	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 11]**

एआईआर 1985 एससी 278	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 12 A]**
(2004) 5 एससीसी 385	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 12]**
जेटी 2007 (13) एससी 436	**पर निर्भर**	**[पैराग्राफ 13]**

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 2539/2009।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा रिटयाचिका (एस) संख्या 6713/2004 के निर्णय और आदेश दिनांक 28.10.2005 से।

बी.बी. सिंह अपीलकर्ता के लिए।

मुश्ताक अहमद (एनपी) उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा** द्वारा दिया गया।1.अनुमति दी गई।

2. दो परिपत्रों की व्याख्या और/या आवेदन; एक 21.9.1987 का और दूसरा 9.8.2000 का, जो मौद्रिक मुआवजे और/या सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति से संबंधित हैं, इस अपील में विचारणीय है जो झारखंड उच्च न्यायालय के एक विभाजन पीठ द्वारा 28.10.2005 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उत्तरदाता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए उचित निर्देश मांगे गए थे।

3.बिहार राज्य ने नक्सलियों और/या चरमपंथियों के हाथों होने वाली बड़ी संख्या में हताहतों को ध्यान में रखते हुए आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक संघर्षों/हिंसा के पीड़ितों को मौद्रिक मुआवजा देने का नीतिगत निर्णय लिया। यह निर्णय उन घटनाओं के संबंध में एक्स-ग्रेटिया भुगतान के रूप में लिया गया था। यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जिसमें आतंकवादी घटनाओं में घायल व्यक्तियों के आश्रितों को एक्स-ग्रेटिया भुगतान देने की बात कही गई थी, जो गया जिले के अर्बल पुलिस स्टेशन में हुई थीं, और इसके अलावा यह भी देखा गया कि इसी तरह की घटनाएं औरंगाबाद जिले के मदनपुर पुलिस स्टेशन बाघौरा और दलेलचुक गांवों में हुई थीं, जिसके अनुसार मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 20,000/- रुपये का भुगतान किया जाना था और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5,000/- रुपये तथा गंभीर चोट की स्थिति में 500/- से 1000/- रुपये का भुगतान किया जाना था।

4.आतंकवादी/संक्रामक या सूचीबद्ध अपराधियों के पक्ष में कोई एक्स-ग्रेटिया भुगतान नहीं किया जाना था। संपत्तियों के विनाश या क्षति की स्थिति में भी मौद्रिक मुआवजे का प्रस्ताव किया गया था, जो उक्त परिपत्रों में उल्लेखित शर्तों के अधीन था। छात्रों की सहायता और घायल व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार जैसी विभिन्न अन्य प्रकार की अनुदान योजनाएं भी इसमें निर्धारित की गई थीं। आकस्मिक खर्चों के माध्यम से अन्य उपाय भी विचार किए गए थे।

5.निर्विवाद रूप से, उत्तरदाता का पिता सरकारी कर्मचारी नहीं था। उन्हें कथित तौर पर 19.5.2000 को चरमपंथियों द्वारा मार दिया गया था। बिहार राज्य ने आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के आश्रितों को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति देने के लिए एक और योजना अपनाई, जैसा कि 9.8.2000 के परिपत्र से स्पष्ट होता है।

> "मुझे यह कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि राज्य में चुनाव/संयुक्त हत्याओं से संबंधित आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक संघर्षों/हिंसा की घटनाएँ हुई हैं और आमतौर पर ऐसे हमलों के प्रभावित लोग निर्दोष व्यक्ति और उनके आश्रित होते हैं। कभी-कभी पूरा परिवार मृतक जैसा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, कल्याणकारी राज्य की सरकार होने के नाते, आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक संघर्ष/हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को एक्स-ग्रेटिया और अन्य सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। राज्य सरकार हमेशा इस दिशा में प्रयास कर रही है। हाल ही में, माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक पारदर्शी नीति निर्धारित करने का आदेश भी दिया है, जो धर्मशिला कुंवर बनाम राज्य सरकार और अन्य (सीडब्लूजेसी संख्या 5808/97) से संबंधित मामले में है।
>
> आज तक, राज्य में आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक संघर्षों के कारण हुई हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों और उनके आश्रितों को गृह (विशेष) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या ए/एन पॉल 1701 दिनांक 21.09.1987 (अनुबंध-1) में किए गए प्रावधानों के अनुसार एक्स-ग्रेटिया स्वीकृत किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार, उपरोक्त प्रकार की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये केवल), स्थायी विकलांगता का सामना करने वालों को 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल) और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 500/- से 1,000/- रुपये (पांच सौ से एक हजार रुपये) एक्स-ग्रेटिया के रूप में स्वीकृत किया गया है, लेकिन यह एक्स-ग्रेटिया किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो संक्रामक/आतंकवादी हो या किसी प्रकार का सूचीबद्ध

अपराधी हो। उक्त परिपत्र में सहानुभूतिपूर्ण आधार पर सरकारी सेवा में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

उक्त नीतिगत निर्णय का पैराग्राफ 7 इस प्रकार है:

"उपरोक्त प्रमुखों में भुगतान के लिए आवश्यक राशि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। निधियों का आवंटन पूर्व की तरह बजट प्रमुख 2235 के तहत किया जाएगा। चुनावों/हत्याओं और किसी अन्य प्रकार की हिंसा से संबंधित आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक संघर्षों के संबंध में राहत उपलब्ध कराने के लिए गृह (विशेष) विभाग उपलब्ध होगा, जहाँ नीति संबंधी सभी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे और राहत कार्य और सरकारी सेवा प्रदान करने की प्रक्रियाओं की निगरानी की जाएगी।"

6. उत्तरदाता, स्व. दुली साहू का पुत्र, ने लगभग 5.11.2000 को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए एक प्रतिनिधित्व दायर किया। इसे उपयुक्त आयुक्त, गुमला द्वारा 25.1.2003 को एक आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि उस समय सरकार के प्रचलित निर्देशों के प्रकाश में मृतक के पुत्र के लिए सहानुभूतिपूर्ण आधार पर रोजगार का कोई प्रावधान नहीं था।

हालांकि, लगभग 7.5.2003 को झारखंड सरकार, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आई, ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि आतंकवादी हिंसा में मृतक के आश्रित की नियुक्ति से संबंधित मामला उन व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होना चाहिए जो झारखंड राज्य के गठन की तारीख, अर्थात् 15.10.2000 के बाद हिंसा में मारे गए थे।

उपरोक्त प्रस्ताव के प्रकाश में, उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व 5.4.2005 को आयोजित जिला सहानुभूति समिति की बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें कहा गया:

"आवेदक स्व. दुली साहू के पिता की हत्या 19.5.2000 को हुई थी, अर्थात् 09.08.2000 से पहले। यह उल्लेखित किया गया है कि बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1972 दिनांक 09.08.2000 के पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि 'यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।'

इस प्रकार, यह मामला बिहार सरकार के परिपत्र और झारखंड सरकार के प्रस्ताव के दायरे में नहीं आता।

इसलिए, समिति ने उक्त मामले को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।"

7. उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए, उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दो समान मामलों के साथ लिया गया। उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ ने विवादित निर्णय में यह राय व्यक्त की कि हालांकि उत्तरदाताओं को मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान किया गया है; लेकिन झारखंड राज्य द्वारा सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्तियों के मामले में जारी परिपत्रों को देखते हुए, जो मृत्यु की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर सामान्य मामलों में लागू होते हैं, यह मामला भी इसी श्रेणी में आएगा, जो इस प्रकार है:

> "मृत्यु की तारीख से निर्धारित पांच वर्षों की यह सीमा और इस प्रकार 25 मई, 1989 के परिपत्र संख्या 6817 ने उन कर्मचारियों के आश्रितों को भी कवर किया है, जो 25 मई, 1989 से पहले मारे गए थे लेकिन पांच वर्षों की सीमा के भीतर थे, जिससे आश्रित को आवेदन करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1986 में सेवा के दौरान मरा, तो उस मृतक कर्मचारी का आश्रित यदि मृत्यु के पांच वर्षों के भीतर आवेदन करता है, तो वह 25 मई, 1989 के परिपत्र द्वारा भी कवर किया जाएगा। उक्त परिपत्र को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापन संख्या 3/सी-2-2067/90 का. 13293 दिनांक 5 अक्टूबर, 1991 द्वारा और स्पष्ट किया गया है।
>
> सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के मामले में, यदि किसी व्यक्ति की हत्या आतंकवादी/चरमपंथी द्वारा या साम्प्रदायिक हिंसा या चुनावी हिंसा आदि के दौरान होती है, तो 'आश्रित' की परिभाषा और सामान्य सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति से संबंधित अन्य चीजों का पालन किया जाना चाहिए; सीमा अवधि वही होगी अर्थात् मृत्यु की तारीख से पांच वर्ष और उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

8. श्री बी.बी. सिंह, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया:

> i. उच्च न्यायालय ने कानून की गंभीर त्रुटि की है क्योंकि उसने यह ध्यान में नहीं रखा कि झारखंड राज्य द्वारा जारी परिपत्रों को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के मामले में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
>
> ii. सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति की योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसे उन मृतकों के आश्रितों के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे।

9.आतंकवादी/संक्रामक/साम्प्रदायिक हमलों में प्रभावित मृतक या घायल व्यक्तियों के आश्रितों को मौद्रिक मुआवजा देने की योजना को उन परिपत्र पत्रों में किए गए प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जिनमें नीतिगत निर्णय शामिल हैं। सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति, यह स्पष्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। ऐसी योजनाओं को व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता क्योंकि संवैधानिक योजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए विचारित होने के योग्य हैं, उन्हें इसके लिए विचारित किया जाएगा। इसलिए, सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति के लिए कोई भी नीतिगत निर्णय सख्त व्याख्या का विषय होना चाहिए।

10.राज्य जम्मू और कश्मीर एवं अन्य बनाम सजाद अहमद मीर [(2006) 5 एससीसी 766] में, कानून निम्नलिखित रूप में स्थापित किया गया:

> "11. हम यह भी अवलोकन कर सकते हैं कि जब उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ आवेदक के मामले पर विचार कर रही थी, जिसने 'सहानुभूति' मांगी थी, तो पीठ को बड़े मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए था और वह यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्यतः, सरकार या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर, सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक कि मजबूर परिस्थितियाँ न हों, जैसे कि एकमात्र भरण-पोषण करने वाले की मृत्यु और परिवार के संकट का सामना करने की संभावना। जब यह साबित हो जाता है कि भरण-पोषण करने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और पर्याप्त समय बीत चुका है, तो सामान्य नियुक्ति के नियम को 'अलविदा' कहने और कई अन्य लोगों के हितों की अनदेखी करते हुए एक को विशेष लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश का उल्लंघन करता है।
>
> [देखें *मुमताज़ युनूस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* [2008 (4) स्केल 637]]।

11.सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति प्रदान करने वाला परिपत्र उन निर्भर व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता जो मृतक सरकारी कर्मचारी नहीं थे। सार्वजनिक रोजगार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो इसके लिए योग्य है। सभी भर्ती उचित अपवादों के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी

चाहिए। राज्य द्वारा जारी किया गया परिपत्र संविधान की सार्वजनिक नियुक्ति की योजना से बाहर नहीं हो सकता। [देखें आधिकारिक लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य [(2008) 10 एससीसी 1 पैराग्राफ 52]; बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह एवं अन्य [(2009) 4 स्केल 282 पैराग्राफ 19]; और मान सिंह बनाम आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी एवं अन्य [2009 (4) एससीसी 645]।

12. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि एक दयालु परिपत्र को उस मामले में नहीं बढ़ाया जा सकता जिसे परिपत्र स्वयं द्वारा नहीं माना गया था।

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचूर बनाम रामानुजा मैच उद्योग [एआईआर 1985 एससी 278] में, इस न्यायालय ने कहा:

> "हम संदेह नहीं करते कि लाभकारी विधान को विधायी इरादे को लागू करने के उद्देश्य से उदार व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन जहां ऐसा लाभकारी विधान अपनी योजना के साथ है, वहाँ न्यायालय को योजना से परे जाने और उन लोगों को वैधानिक लाभ का विस्तार करने के बहाने से अधिनियम के दायरे को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है जो योजना के अंतर्गत नहीं आते।"

दीपाल गिरिशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा [(2004) 5 एससीसी 385] में, यह राय व्यक्त की गई:

"53. हालांकि यह अधिनियम लाभकारी है और इसलिए इसे विधायी इरादे को लागू करने के उद्देश्य से उदार व्याख्या की आवश्यकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जहां ऐसा लाभकारी विधान अपनी योजना के साथ है और उसमें कोई अस्पष्टता या संदेह नहीं है, न्यायालय उसी तक सीमित रहेगा और अधिनियम के दायरे को उन लोगों को वैधानिक लाभ का विस्तार करने के बहाने से नहीं बढ़ाएगा जो इसके अंतर्गत नहीं आते।"

13. इसके अलावा, अधीनस्थ कानून के निर्माण या आवेदन के मामले में, संदर्भ द्वारा समावेशन का नियम तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक कि इसके लिए स्पष्ट मामला प्रस्तुत न किया जाए। 21.9.1987 का परिपत्र स्वतंत्र है। यह अपने क्षेत्र में कार्य करता है। दोनों परिपत्रों को एक साथ पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि उन्हें पढ़ा भी जा सके, तो सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्तियों के संबंध में सामान्य परिपत्र, जो मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के मामलों में लागू होते थे, न तो उन नियुक्तियों की अवधि पर विचार करने के लिए और न ही अन्यथा, लाभ देने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए वह अन्यथा योग्य नहीं था।

भारतीय बैंक प्रबंधन एवं अन्य बनाम रामचंद्रन [जेटी 2007 (13) एससी 436] में यह कहा गया है:

> "यह अब एक सामान्य कानून है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करने के उद्देश्य से किसी अन्य अधिनियम का संदर्भ लेना अनुमेय नहीं है और इस प्रकार, सिविल सेवाओं के पेंशन नियमों का विनियमन 21 एक अलग स्थिति की कल्पना करता है, इसका इस मामले में कोई आवेदन नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान पर निर्भर रहकर त्रुटि की।"

14. सामान्यतः, अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं समझा जाना चाहिए। 7.5.2003 का परिपत्र भविष्यात्मक प्रभाव दिया गया था। उत्तरदाता के पिता की मृत्यु 19.5.2000 को हुई। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि 9.8.2000 का परिपत्र भी पूर्वव्यापी प्रभाव में दिया गया था। किसी भी दृष्टिकोण से, चूंकि झारखंड राज्य ने 7.5.2003 के परिपत्र में बिहार राज्य द्वारा जारी किए गए पूर्ववर्ती परिपत्रों को केवल उन मामलों में अपनाया जहां मृत्यु 15.10.2000 के बाद हुई थी, अर्थात् उस तारीख से जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव देने में गंभीर त्रुटि की, जिसे वह सीधे तौर पर नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण, उपरोक्त कारणों के लिए, अस्वीकार्य हैं।

15.उपरोक्त कारणों के लिए, विवादित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता, जिसे इस प्रकार निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|